(क) वर्ष 1990 की तुलना में 1992 और 1993 के वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की उपयोग की गई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) 1994 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991 में खाद्य तेलों की समग्र क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत के लगभग था । खाद्य तेल उद्योग को 25 जुलाई, 1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। अतः तब से खाद्य तेलों की क्षमता के उपयोग के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । हालांकि स्थिति में कोई सुधार आया प्रतीत नहीं होता है।

(ख) पूर्ण क्षमता का उपयोग न करने का एक मुख्य कारण, कच्ची सामग्री की उपलब्धता के मुकाबले, उद्योग को बेमेल वृद्धि होना प्रतीत होता है।

(ग) खाद्य तेलों के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं है । यह कृषि मंत्रालय द्वारा परिकल्पित तिलहनों के उत्पादन के लक्ष्य पर निर्भर करता है।

Changing the sizes of packages

1839. SHRI AJIT P.K. JOGI :
SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has changed package sizes in the recent Draft Notification at the behest of the multinational soft drink companies without protecting the consumers' interests ;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) what are the steps being taken to prevent such issues in order to protect the consumers' interests ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Exclusion of Doctors and Private Hospitals from the consumer protection Act

1840. SHRI G.Y. KRISHNAN :

SHRI SHIV PRATAP MISHRA :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Madras High Court's recent judgement exempting Doctors and private Nursing Homes from the purview of the Consumer Protection Act ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and steps proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) Reports on the Madras High Court judgement have appeared in the newspapers. Official communication is awaited. Similar cases are pending before other High Courts and the Supreme Court.

Women Sales Assistant in Super Bazar

1841. SHRI SARADA MOHANTY :
Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what is the total strength of women sales assistants in Super Bazar as on date, branchwise ;

(b) the details of women sales Assistant viz. their names, date of birth, qualifications, date of appointment and marital status ;

(c) the number of applications received so far by the Super Bazar management from women applicants for the said post :

(d) how many out of them have so far been considered and appointed and status of the remaining pending applications ;

(e) whether the Super Bazar Management is maintaining separate seniority list of women sales assistant for promotion ; and

(f) the number of women sales assistants promoted during last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) Super Bazar has informed that as on 1-3-94, the total number of women Sales Assistants was 89 and they were posted in 26 branches including Head Office at Connaught Place. It is considered that the labour involved in collection and tabulation of the data relating to names of each woman sales assistant, date of birth, qualification, date of appointment and marital status will not be commensurate with the results to be achieved therefrom.

(c) There has been a ban on recruitment in Super Bazar and as such no applications for fresh appointment are entertained.

(d) In view of the reply given in part (c) question does not arise.

(e) No, Sir.

(f) Super Bazar has informed that 14 women sales assistants have been promoted during the last three years.

खाद्य तेलों के आयात बिल में कटौती

1842. **चौधरी हरि सिंह** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1993-94 के दौरान तेल के आयात बिल में कटौती करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं ;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1992-93 में तेल के आयात बिल में कितने प्रतिशत कटौती की गई ;

(घ) 1993-94 के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) खाद्य तेलों की उपलब्धता एवं मूल्यों की समीक्षा करना एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा यदि आवश्यक हो तो खाद्य तेलों के आयात का निर्णय, मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर, बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों, तिलहनों की भावी/आगामी फसलों की संभावनाओं इत्यादि जैसे संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान, जब खाद्य तेलों की कीमतें जुलाई–अक्तूबर, 93 के दौरान दबाव में थी, तथा त्यौहार के महीनों के लिए खाद्य तेलों की बढ़ी हुई मांग प्रत्याशित थीं, सरकार ने वर्ष के दौरान एक लाख मी० टन पामोलीन का आयात करने का निर्णय किया। इसमें से, राज्य व्यापार निगम द्वारा अब तक लागत, बीमा तथा भाड़ा मूल्य सहित 50.88 करोड़ रु० मूल्य की 42,000 मी० टन (लगभग) मात्रा का आयात किया जा चुका है। राज्य व्यापार निगम द्वारा 1991-92 के दौरान 103.73 करोड़ रुपये के लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य पर किए गए 1.07 लाख मी० टन पामोलीन के आयात के मुकाबले राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1992-93 के दौरान 39.44